(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

जसजीत सिंह बेदी जे. के समक्ष

विरेंद्र कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य प्रतिवादीगण

2018 का सी. आर. एम.-ए. संख्या 1313-एम. ए. (ओ. एंड एम.)

1 दिसंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 378-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 306, 107-निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील-आरोप लगाया गया कि मृतक व्यथित रहा क्योंकि उसने अभियुक्त संपत्ति विक्रेताओं को भूखंडों की खरीद के लिए पैसे दिए थे, जिन्हें उन्होंने न तो खरीदा था और न ही पैसे वापस किए थे-घटना के दिन, मृतक ने परिवार से कहा कि वह पैसे लेने जा रहा था-इसके बाद नहर में कूद गया और अपनी जान ले ली-यह सवाल उठाया गया कि क्या अभियुक्त की कथित कार्रवाई भ.द.स. की धारा 306 के तहत उकसाने का अपराध है-एस. एस. की पृष्ठभूमि में मामले की जांच करने पर यह माना गया कि 107 और 306, कोई अपराध नहीं किया जाता है-अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य न तो पुरुष कारण साबित करता है, न ही कोई प्रत्यक्ष या सक्रिय कार्य साबित करता है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की। पुरे अभियोजन संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर सही मानते हुए,भारतीय दंड सहिता की धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं माना जाएगा-जब विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त होने का आदेश पारित कर दिया है, तो अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है-विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर-विवादित निर्णय विकृत नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है-खारिज कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्पि अपीलीय न्यायालय को उन साक्ष्य की समीक्षा करने, पुनः मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया है, यह भी उतना ही सत्य है कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है, पहला किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध निर्दोषता की धारणा के कारण और दूसरा इस तथ्य के कारण कि सक्षम न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया है और इसलिए, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव थे, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्त करने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए, केवल इसलिए कि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की तुलना में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। हालाँकि, जहाँ निर्णय के खिलाफ अपील की गई है वह पूरी तरह से विकृत है और निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं या अस्वीकार्य सामग्री, तब अपीलीय न्यायालय उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें दरकिनार करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा।

(पैरा 16)

आगे अभिनिर्धारित किया कि इसके ऊपर की विस्तृत चर्चा के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को देखते हुए, अभियुक्त को बरी करते समय विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर एक उचित दृष्टिकोण है, जिसे विकृत नहीं कहा जा सकता है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशित मलिक।

नीरज पोसवाल, सहायक,ए.जी,हरियाणा।

जस्जीत सिंह बेदी, जे। (मौखिक)

(1) आवेदक/अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश दिनांक 19.12.2017 के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया है, जिसमें अभियुक्त-प्रतिवादी No.2/जगदीश ढींगरा @पप्पु को भारतीय दंड सहिता की धारा 306 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 17.08.2015 पर, टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि देवेंद्र उर्फ रिंकू की मौत गाँव उदार्सी के पास भाखड़ा नहर में डूबने से हुई थी।जब उपनिरीक्षक चानन राम, ए. एस. आई. राज कुमार, ए. एस. आई. नरेश कुमार, एच. सी. मनोज कुमार के साथ भाखड़ा नहर गांव उदारसी की ओर बढ़ रहे थे, तो शिकायतकर्ता विरेंद्र कुमार और डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस स्टेशन, शाहाबाद के गेट के सामने शिकायत दर्ज कराई।शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रोशन लाल की आटा मिल के पास मोहल्ला खटेरवाड़ा के हाउस नंबर.227/4 का निवासी था और वे दो भाई थे।वह देवेंद्र उर्फ रिंकू से बड़ा था, जो शादीशुदा था और कपड़े का व्यवसाय करता था।उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, चार से पाँच महीने पहले, देवेंद्र उर्फ रिंकू ने प्रॉपर्टी डीलर जगदीश उर्फ पप्पु ढींगरा जो देसराज का बेटा है ने निवासी तांगे वाली गली, माजरी मोहल्ला, शाहाबाद मार्कंडे को एक भूखंड की खरीद के लिए 6,00,000/- रुपये और प्रॉपर्टी डीलर करम सिंह के बेटे गुरजीत सिंह को 8 लाख कि राशि दी थी । यह पैसा उनकी कंपनी से दिया गया था। भुगतान के बावजूद, दोनों अभियुक्तों ने अपने भाई के लिए कोई भूखंड नहीं खरीदा और न ही पैसे वापस किए। उसका भाई परेशान रहता और अपना पैसा खोने के डर से तनाव में रहता। दिनांक 17.8.2015 को, सुबह लगभग 6.15 बजे, उनके भाई एक स्विफ्ट कार में घर से निकले, जिसका पंजीकरण नंबर एच.आर.78-9191 है, जाते समय उसने कहा कि वह पैसे इकट्ठा करने जा रहा है। सुबह करीब 8.15 बजे उन्हें (शिकायतकर्ता) टेलीफोन पर सूचना मिली कि उनकी (मृतक की) कार डल्ला माजरा गांव में नहर के पास खड़ी है और कार के पास एक चाबी के साथ चप्पल पड़ी है।वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा जहां उसे पता चला कि देवेंद्र उर्फ रिंकू ने नहर में डूबकर अपनी जान दे दी है।उसके भाई ने आरोपी जगदीश उर्फ पप्पु और गुरजित सिंह के

उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी।बाद में, उरसी गांव के पास नहर से शव बरामद किया गया।वे शव को सिविल अस्पताल, कुरुक्षेत्र ले गए।दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रार्थना की गई।

(3)प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच की गई और धारा 173 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

(4) अभियुक्त के खिलाफ भ.द.स की धारा 306 के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, उसे अदालत द्वारा दिनांकित 19.08.2016 के आदेश के माध्यम से आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(5) अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता पीडब्लू-1 विरेंद्र कुमार से पूछताछ की, जिन्होंने अपनी शिकायत प्रदर्शनीय-पी1 के आधार पर गवाही दी, जिसे उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई का शव भाखड़ा नहर से उदारसी के पास मिला था और पुलिस ने धारा 175 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत उनके दोस्त सुशील कुमार और उनके मामा ओम प्रकाश के बयान दर्ज किए। उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने शव की पहचान की, जिसे रसीद प्रदर्शनीय-पी2 के माध्यम से उन्हें दिया गया।पुलिस ने एक प्लास्टिक की बोतल में नहर से पानी लिया जिसे रिकवरी मेमो प्रदर्शनीय-पी3 के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। ज्ञापन प्रदर्शनीय-पी4 के माध्यम से चप्पल की एक जोड़ी के साथ पंजीकरण एच.आर.78-9191 वाली स्विफ्ट कार को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रदर्शनीय-पी3 थी।गाड़ी की तलाशी ली गई और ज्ञापन प्रदर्शनीय-पी6 तैयार किया गया।वे कार को सुपरदारी वीडियो मेमो प्रदर्शनीय-पी7 पर ले गए।पुलिस द्वारा उनके मामा ओम प्रकाश का बयान प्रदर्शनीय-पी8 दर्ज किया गया था।उन्होंने अपने मामा ओम प्रकाश के हस्ताक्षर प्रदर्शनीय-पी2, प्रदर्शनीय-पी4, प्रदर्शनीय-पी6, प्रदर्शनीय-पी7 और प्रदर्शनीय-पी8, चप्पल प्रदर्शनीय-पी9 और प्रदर्शनीय-पी10 पर मृतक द्वारा 17.08.2015 पर पहने जाने की पहचान की और कहा कि वे कार के पास पड़े हुए पाए गए थे।उन्होंने कहा कि उनके भाई देवेंद्र उर्फ रिंकू ने आरोपी जगदीश ढींगरा उर्फ पप्पु और गुर्जर सिंह द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली।उनके भाई ने जिन मोबाइल फोन नंबरों का इस्तेमाल किया वे 9896327235 और 9254000034 थे जबकि उनके मोबाइल फोन नंबर 9416292759 और 9996139459 थे।उसका भाई आरोपी व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के कारण अवसाद में था और वह उसे, अपनी पत्नी और माँ को उत्पीड़न के बारे में बताता था। मृतक देवेंद्र ने परिवार के सभी सदस्यों को सभी तथ्य बताए और उन्हें कोई समाधान खोजने के लिए कहा।

पीडब्लू-2 प्रेम सिंह, कैनाल पटवाड़ी ने घटना स्थल, गाँव डल्ला माजरा, नरवाना शाखा नहर की स्केल्ड साइट योजना प्रदर्शनीय-पी11 को साबित किया, जिसे उन्होंने एस. आई. चानन राम के सीमांकन पर 30.09.2015 पर तैयार किया था।

पीडब्लू-3 ईएचसी राजेश कुमार ने बिना किसी देरी के इलाका न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र और पुलिस उपाधीक्षक, शाहाबाद को मामले की विशेष रिपोर्ट सौंप दी।

पीडब्लू-4 प्यारे लाल, नहर के पटवार हलका ज्योतिसर ने एस. आई. चनन सिंह के सीमांकन पर 30.09.2015 पर स्केल्ड साइट प्लान प्रदर्शनीय-पी12 तैयार किया।

पीडब्लू-5 एएसआई अजमेर सिंह ने विरेंद्र कुमार की शिकायत पर 17.08.2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनीय-पी13 दर्ज की।उन्होंने शिकायत पर अपना समर्थन प्रदर्शनीय-पी 14 साबित किया और कहा कि उन्होंने ई. एच. सी. राजेश कुमार के माध्यम से उच्च अधिकारियों को विशेष रिपोर्ट भेजी।

पीडब्लू-6 सी. करमबीर ने कहा कि 18.08.2015 पर, मृतक देविंदर @रिंकू के मोबाइल फोन नंबर 98963-27235 और 92540-00034, मृतक की मां राजरानी का मोबाइल फोन नंबर 85720-94272 और शिकायतकर्ता विरेंद्र का मोबाइल फोन No.99961-39459 के कॉल विवरण रिकॉर्ड और पते लेने के लिए प्रभारी पुलिस पोस्ट सिटी शाहाबाद द्वारा आवेदन प्रदर्शनीय-पी 15 को प्रभारी साइबर सेल, कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।उन्होंने ईमेल के माध्यम से संबंधित सेवा प्रदाताओं से कॉल विवरण रिकॉर्ड प्राप्त किया और प्रिंट-आउट प्रदर्शनीय-पी 16 को प्रदर्शनीय-पी 18 और धारकों के पते वाली सूची प्रदर्शनीय-पी 19 एस. आई. चनन राम जांच अधिकारी को सौंप दी, जिन्हें ज्ञापन प्रदर्शनीय-पी 20 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।उनका बयान एस. आई. चानन राम ने दर्ज किया।

पीडब्लू-7 एच. सी. अजय ने विसरा का एक सीलबंद पार्सल, निदेशक, एफ. एस. एल. मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा और निदेशक, एफ. एस. एल. मधुबन के साथ डॉक्टर की नमूना मुहर 27.08.2015 पर जमा की और रसीद एम. एच. सी. करमबीर को वितरित की।उन्होंने आगे कहा कि 01.09.2015 पर, एम. एच. सी. करमबीर ने उन्हें मृतक के रक्त से भरी एक सीलबंद शीशी, निदेशक, एफ. एस. एल. मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा, डॉक्टर की नमूना मुहर और एक सीलबंद पानी की बोतल के साथ-साथ जांच अधिकारी की नमूना मुहर निदेशक, एफ. एस. एल. मधुबन के पास जमा करने के लिए सौंपी।उन्होंने उसे एफ. एस. एल. मधुबन में जमा किया और रसीद एम. एच. सी. करमबीर को सौंप दी। जिस अवधि के दौरान मामले की संपत्ति उनके पास रही, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की।

पीडब्लू-8 डॉ. संजीव शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र ने अपना विधिवत शपथ पत्र प्रदर्शनीय-पी21 को साक्ष्य प्रस्तुत किया जिस में दिलबाग राय के बेटे देवेंद्र कुमार के शव पर पोस्टमॉर्टम जांच के संबंध में पोस्टमॉर्टम जांच के समय नोट की गई चोटें और पुलिस को सौंपी गई सामग्री थी। उन्होंने पीएमआर प्रदर्शनीय-पी 22 की प्रति साबित की और उस पर डॉ. गौरव चावला के हस्ताक्षरों की पहचान की। एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्रदर्शनीय-पी 23 और प्रदर्शनीय-पी 24 देखने के बाद, उन्होंने कहा कि देवेंद्र की मृत्यु का कारण पानी में डूबना था, न कि कोई सामान्य जहर।उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम करने के बाद विसरा वाला एक सीलबंद डिब्बा, निदेशक, एफएसएल, मधुबन को संबोधित एक सीलबंद लिफाफा, खून की एक सीलबंद शीशी और दो नमूना मुहरें सब इंस्पेक्टर चनन राम को सौंप दी गईं।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

पीडब्लू-9 एच.सी. करमबीर ने कहा कि दिनांक 17-08-2015 को एस.आई. चानन राम प्रभारी पुलिस चौकी हुडा, शाहाबाद ने अपने साथ एक सीलबंद डिब्बा, रक्त की एक सीलबंद शीशी, निदेशक, एफएसएल मधुबन को संबोधित दो लिफाफे, डॉक्टरों की दो नमूना मुहरें, एक सीलबंद पानी की बोतल और जांच अधिकारी की एक नमूना मुहर जमा की, जिसे उन्होंने रजिस्टर संख्या 19 में क्रम संख्या 396/15 पर दर्ज किया। उन्होंने कहा कि 27.08.2015 को उन्होंने एफ. एस. एल. मधुबन में जमा करने के लिए ई. एच. सी. अजय कुमार को एक सीलबंद डिब्बा, एक लिफाफा, एक नमूना मुहर सौंपी, जिन्होंने उसी दिन एफ. एस. एल. मधुबन में जमा किया और उसे रसीद दी। उन्होंने कहा कि 01.09.2015 को उन्होंने एफ. एस. एल. मधुबन में जमा करने के लिए ई. एच. सी. अजय कुमार को रक्त की एक सीलबंद शीशी, एक लिफाफा, एक नमूना मुहर, एक पानी की बोतल और जांच अधिकारी की एक नमूना मुहर सौंपी। उसी दिन उन्होंने उसे एफएसएल मधुबन के पास जमा कर दिया और रसीद उन्हें सौंप दी। उनके पास रहने की अवधि के दौरान मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

पीडब्लू10 डॉ. प्रिया चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, फोरेंसिक प्रयोगशाला, मधुबन ने जीव विज्ञान प्रभाग, एफएसएल, मधुबन में कांस्टेबल अजय कुमार के माध्यम से दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त रक्त नमूने की एक शीशी और पानी के नमूने की एक बोतल वाले सीलबंद पार्सल पर नमूने की जांच परीक्षण की जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, शाहाबाद के अनुरोध पर जांच की गई।उन्होंने कहा कि रक्त के नमूने की एक शीशी और पानी के नमूने की जांच परीक्षण की एक बोतल वाले पार्सल में मुहरें बरकरार थीं और प्रदर्शनीय-1 रक्त के नमूने और प्रदर्शनीय-2 पानी के नमूने की जांच की गई थी जो समान प्रकार के पाए गए थे। उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्शनीय-पी 23 दी और जाँच के बाद, पार्सल को फिर से 'पी. सी. एफ. एस. एल.' मुहर से सील कर दिया गया। उसने पानी की बोतल प्रदर्शनीय-पी25 साबित की जिस पर उसकी मुहर 'पीसी एफएसएल' थी।

पीडब्लू-11 मृतक के पिता दिलबाग राय, मृतक के मामा पीडब्लू-12 ओम प्रकाश और मृतक की पत्नी पीडब्लू-13 किरण ने विरेंद्र कुमार पीडब्लू-1 के बयान की पुष्टि की जो आरोपी जगदीश ढींगरा उर्फ पप्पु द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण मृतक देवेंद्र उर्फ रिंकू द्वारा आत्महत्या के संबंध में, जिसने न तो 6 लाख रुपये लौटाए और न ही उसके लिए कोई संपत्ति खरीदी।

पीडब्लू-14 इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने जांच पूरी होने पर 24.09.2015 पर धारा 173 (2) दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत रिपोर्ट तैयार की.

पीडब्लू-15 मामले की जांच करने वाले एस. आई. चानन राम ने कहा कि उन्हें 17.08.2015 उसको एक टेलीफोनिक संदेश मिला कि देवेंद्र सिंह की मौत गाँव उदार्सी के पास भाखड़ा नहर में डूबने से हुई है। जब वे गाँव उदार्सी जा रहे थे, शिकायतकर्ता विरेंद्र ने उनसे पुलिस स्टेशन, शाहाबाद के पास मुलाकात की और एक आवेदन प्रदर्शनीय-पी1 प्रस्तुत किया जिसमें जगदीश ढींगरा और गुरमीत सिंह द्वारा अपने भाई देवेंद्र को लगातार

परेशान करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उन्होंने भाखड़ा नहर में आत्महत्या कर ली।उन्होंने पुलिस कार्यवाही प्रदर्शनीय-पी 29 की और ए. एस. आई. नरेश कुमार को मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन, शाहाबाद भेजा।फिर वह ए. एस. आई. राज कुमार और एच. सी. मनोज कुमार के साथ एल. एन. जे. पी. अस्पताल, कुरुक्षेत्र पहुंचे और धारा 174 द.प.स. के तहत जांच परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शनीय-पी30 पेश की। उन्होंने सुशील कुमार और ओम प्रकाश के बयान धारा 175 द.प.स. के तहत दर्ज किए। फिर वे ए. एस. आई. नरेश कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, यानी गाँव उदार्सी और बचगांव के पास भाखड़ा नहर और विरेंद्र कुमार के कहने पर रफ साइट प्लान प्रदर्शनीय-पी31 तैयार किया। उसने नहर से पानी की बोतल प्रदर्शनीय-पी 32 ली, उसे सील 'SR' से सील कर दिया और मेमो प्रदर्शनीय-पी 3 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया। फिर, वह ओम प्रकाश के साथ गाँव डल्ला माजरा गए।पंजीकरण एच.आर.78-9191 वाली एक स्विफ्ट कार वहाँ खड़ी थी।कार की चाबी और सैंडल की एक जोड़ी प्रदर्शनीय-पी 10 भी मिली। मेमो प्रदर्शनीय-पी4 के माध्यम से कार, चाबी और सैंडल को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।उन्होंने कहा कि कार के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्शनीय-पी 5 थी। मेमो प्रदर्शनीय-पी 6 के माध्यम से कार की तलाशी ली गई। कार शिकायतकर्ता विरेंद्र और ओम प्रकाश को मेमो प्रदर्शनीय-पी 7 के माध्यम से सुपरदारी पर दी गई थी। नक्शा मौका बिना सकेली प्रदर्शनीय-पी 33 तैयार किया गया था। एएसआई राज कुमार ने उन्हें विसरा वाला एक सीलबंद पार्सल, एक रक्त की शीशी और एक अन्य सीलबंद जार के साथ नमूना मुहर और लिफाफा सौंपा, जिसे उन्होंने एमएचसी, पुलिस स्टेशन, शाहाबाद में जमा किया। 18.08.2015 पर, आवेदन प्रदर्शनीय-पी 15 को प्रभारी साइबर सेल, एस. पी. कार्यालय, कुरुक्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें उसमें उल्लिखित मोबाइल नंबरों का विवरण मांगा गया था। 22.08.2015 को कॉल विवरण प्रदर्शनीय-पी 34 आईडी के साथ कांस्टेबल करमवीर द्वारा दिया गया था, जिसे मेमो प्रदर्शनीय-पी 20 के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया था।देवेंद्र का शव ओम प्रकाश और सुशील कुमार को ज्ञापन प्रदर्शनीय-पी 2 के माध्यम से सौंप दिया गया।

(6) अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू डॉ. गौरव चावला, राज रानी, सुरजीत उर्फ सुशील कुमार और एएसआई नरेश कुमार को अनावश्यक होने के कारण छोड़ दिया।इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया।

(7) अभियुक्त का बयान धारा 313 द.प.स. के तहत दर्ज किया गया था। उसने अपराध साबित करने वाले साक्ष्य को गलत बताते हुए इनकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

(8) बचाव में, प्रदर्शनीय-डी 2, धारा 161 द.प.स. के तहत दर्ज किरण के बयान की प्रतिलिपी पेश की गई।

(9) निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि साक्ष्य और आरोपों को सच मानते हुए, आरोपी की ओर से कोई अपराधिक मनोसिथित साबित नहीं हुई और इस तरह उसे दिनांक 19.12.2007 के फैसले के माध्यम से बरी कर दिया गया और वह वर्तमान अपील दायर कर सकता है।

(10) आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि पीडब्लू-1/विरेंद्र कुमार (शिकायतकर्ता), मृतक के भाई और पीडब्लू-11/दिलबाग राय (मृतक के पिता) ने अदालत में गवाही देते हुए पुलिस के समक्ष अपना पक्ष

दोहराया और स्पष्ट रूप से कहा कि देवेंद्र @रिंकू (मृतक) ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि आरोपी भूखंड खरीदने के लिए उसके द्वारा दिए गए पैसे को वापस करने में विफल रहा था। वास्तव में, आरोपी व्यक्ति मृतक को धमकी दे रहे थे कि अगर उसने उसके पैसे वापस मांगे तो वे उसे मार देंगे और इसी कारण से आरोपी द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकी दिए जाने के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली। पीडब्लू-13/किरण (मृतक की विधवा) ने भी शिकायतकर्ता-पीडब्लू-1 के बयान के अनुरूप अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। इस प्रकार, वह तर्क देता है कि बरी करने का निर्णय इसके विपरीत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है और बरी किए गए आरोपी को विचाराधीन अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

(11) मैंने आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

(12) आगे बढ़ने से पहले भ.द.स. की धारा 306 और भ.द.स. की धारा 107 के प्रावधानों की जांच करना उचित होगा जो यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

भारतीय. दंड. सहिंता **की धारा 306 निम्नानुसार हैः-**

“306. आत्महत्या के लिए उकसाना।- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।”

आई. पी. सी. की धारा 107 निम्नानुसार हैः

“किसी चीज़ का प्रोत्साहनःएक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, जोः

पहला-किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; या, दूसराःउस कार्य को करने के लिए किसी भी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या तीसरा-जानबूझकर, किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा, उस कार्य को करने में सहायता करता है।”

(13) उकसाने का अर्थ है किसी को ऐसा करने के लिए अंकुश, प्रबल इच्छा, या प्रोत्साहित करना।यह आवश्यक नहीं है कि बहकाने के लिए व्यक्त शब्दों का उपयोग किया जाए। बहकाने से भड़कने का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो उकसाता है न कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर जो इस तरह से उकसाया गया है। इन सभी शब्दों के पीछे की मूल भावना, अर्थात उकसाना, उकसाना, सहायता करना, उकसाना या प्रोत्साहित करना, उन कार्यों या चूक में निहित है जो अभियुक्त ने शब्दों या इशारों से किए ताकि व्यक्ति को ऐसी मानसिक स्थिति में लाया जा सके कि ऐसी परिस्थितियों में, वह परिस्थितियों से इतना मजबूर होकर अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था।

(14) जब वर्तमान मामले की जांच भारतीय दंड सहिता की धारा 107 और भारतीय दंड सहिता की धारा 306 की पृष्ठभूमि में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि कोई भी अपराध नहीं बनाया गया है।

पीडब्लू-1 विरेंद्र कुमार (मृतक के भाई), पीडब्लू-11/दिलबाग राय (मृतक के पिता) और पीडब्लू-13/किरण (मृतक की पत्नी) द्वारा लगाए गए आरोपों का समन और सार यह है कि मृतक-देवेंद्र उर्फ रिंकू ने बरी किए गए आरोपी-जगदीश ढींगरा को एक भूखंड खरीदने के लिए 6 लाख रुपये की राशि दी थी और जब भी वह आरोपी से अपने पैसे या भूखंड वापस मांगता था, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी और पैसे वापस नहीं किए जाते थे।इस वजह से मृतक (देवेंद्र @रिंकू) अवसाद में था जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।वास्तव में, इन गवाहों के बयानों में काफी सुधार हुआ है।धारा 161 द.प.स. के तहत दर्ज प्रारंभिक बयानों में, आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख नहीं मिलता है।यह संस्करण पहली बार आया है जब न्यायालय में उक्त गवाहों से पूछताछ की गई। इसलिए, बेहतर संस्करण को रूप में अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता है।

6 लाख रुपये की अग्रिम राशि के आरोपों को सही मानते हुए, यदि उक्त राशि मृतक को वापस नहीं की जा रही थी, तो उसके पास अदालत या जांच एजेंसियों से संपर्क करके कानून के अनुसार वसूली करने का विकल्प था। केवल इसलिए कि उक्त राशि वापस नहीं की जा रही थी या उक्त राशि से खरीदा जाने वाला प्रस्तावित भूखंड मृतक को नहीं दिया जा रहा था, यह उकसाने का मामला नहीं होगा।

यह कहने के बाद, यह इंगित किया जा सकता है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक ने वास्तव में भूखंड की खरीद के लिए आरोपी को 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था।मृतक के परिवार के तीन सदस्यों-देवेंद्र @रिंकू का अभियुक्त को पैसे देने के संबंध में बयान भी एक दूसरे के विपरीत चल रहा है।पीडब्लू-1/विरेंद्र कुमार ने कहा है कि बैंक से पैसे निकालकर आरोपी को पैसे दिए गए थे और पीडब्लू-11/दिलबाग राय ने कहा है कि उसके बेटे ने अपनी मां से पैसे लेकर आरोपी को 6 लाख रुपये दिए हैं।

चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत कॉल विवरण रिकॉर्ड के साथ कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी और मृतक के बीच कॉल का आदान-प्रदान हुआ था और इस कारण से भी आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर सही मानते हुए भ.द.स.धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को एक कार्य करने के लिए दूसरे को उकसाने के लिए कहा जाता है, जब वह उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम या भाषा से कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से सुझाव देता है या प्रेरित करता है, चाहे वह स्पष्ट अनुरोध या संकेत, आक्षेप या प्रोत्साहन का रूप ले। एक व्यक्ति उकसाकर सहायता करता है जब किसी कार्य से पहले या उसके करने के समय किए गए किसी कार्य द्वारा, वह सुविधा प्रदान करने का इरादा रखता है और वास्तव में उसे करने में सुविधा प्रदान करता है।इरादा किसी अपराध में सहायता करने या अपराध करने में सहायता करने का होना चाहिए। इस मामले में, धारा 173 द.प.स. के तहत रिपोर्ट में कोई सीधा आरोप नहीं है कि आरोपी ने कभी उकसाया, संलग्न किया, जानबूझकर किया या इस तरह की साजिश रची कि मृतक को आत्महत्या कर लेनी चाहिए।सबूत में पीडब्लू-13 किरण का बयान कि आरोपी ने मृतक को जाने और आत्महत्या करने के लिए कहा था, एक अलंकृत विचारशील संस्करण है और अन्यथा भी आरोपी पर अपराध थोपने के लिए अपर्याप्त है। **संजू @संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश के मामले में** प्रदेश

1, जहाँ अभियुक्त ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और मृतक को 'जाने और मरने' के लिए कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उकसाहट पैदा नहीं की गई थी और झगड़े में या पल भर में बोले गए शब्दों को किसी भी अपराधिक मन: स्थिति के साथ नहीं लिया जा सकता है।

स्वामी प्रहलादास बनाम एम. पी. राज्य और अन्य 2, अभियुक्त

उन पर भा. द. स की धारा 306 के तहत इस आधार पर अपराध का आरोप लगाया गया था कि झगड़े के दौरान उन्होंने मृतक को 'जाकर मरने' के लिए कहा था। अदालत का मानना था कि आरोपी द्वारा मृतक को 'जाने और मरने' के लिए कहे गए केवल शब्द ही प्रथम दृष्टया मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, पीडब्लू-1/शिकायतकर्ता-विरेंद्र कुमार, पीडब्लू-11 दिलबाग राय और पीडब्लू-13 किरण के बयानों का उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने अपने निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य न तो आरोपी की ओर से अपराध करने के लिए किसी भी किसी भी अपराधिक मन: स्थिति के साथ नहीं लिया जा सकता है को साबित करता है और न ही किसी भी प्रत्यक्ष या सक्रिय कार्य को साबित करता है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली।

(15) बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में कानूनी स्थिति और न्यायालय द्वारा आहूत हस्तक्षेप की गुंजाइश के संबंध में, एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

“(16) धारा 423 (1) अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को उसके समक्ष प्रस्तुत अपीलों के निपटारे में निर्धारित करती है और खंड (ए) और (बी) क्रमशः दोषसिद्धि के खिलाफ दोषमुक्ति और अपीलों के खिलाफ अपीलों से संबंधित हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति, जो दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित है, खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति के रूप में व्यापक है, जो दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित है, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि आपराधिक अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां समान रूप से व्यापक हैं चाहे विचाराधीन अपील दोषमुक्ति के खिलाफ हो या दोषसिद्धि के खिलाफ।यह सवाल का एक पहलू है।प्रश्न का दूसरा पहलू उस दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिसे उच्च न्यायालय बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपीलों से निपटने में अपनाता है।इस तरह की अपीलों से निपटने में, उच्च न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखता है और हार नहीं सकता है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अनुमान निचली अदालत द्वारा उसके पक्ष में पारित बरी करने के आदेश से मजबूत होता है और इसलिए, यह तथ्य कि आरोपी व्यक्ति एक उचित संदेह के लाभ का हकदार है, हमेशा उच्च न्यायालय के दिमाग में मौजूद रहेगा जब वह मामले के गुण-दोष पर विचार करता है।एक अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय आम तौर पर निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा होता है, विशेष रूप से जब उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित होता है क्योंकि निचली अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का लाभ होता है। जिन्होंने **सबूत दिए हैं। इस प्रकार, हालांकि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय की**

शक्तियां उतनी ही व्यापक हैं जितनी कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर विचार करने में उसके पास हैं, अपीलों के पूर्व वर्ग के साथ व्यवहार करते हुए, इसका दृष्टिकोण अनुमान से बहने वाले प्रबल विचार द्वारा नियंत्रित होता है। निर्दोषता में कभी-कभी, शक्ति की व्यापकता पर जोर दिया जाता है, जबकि अन्य अवसरों पर, बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, और समय-समय पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों या वाक्यांशों में जोर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक कानूनी स्थिति यह है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण चाहे कितना भी सतर्क और सतर्क क्यों न हो, वह निस्संदेह अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार है।इस स्थिति को शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट, (1934) एल. आर. 61 आई. ए. 398 में प्रिवी काउंसिल द्वारा स्पष्ट किया गया हैःए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 और नूर मोहम्मद बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 151।

1 2002 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 687 (एस. सी.)

2 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 943

(17) हालाँकि, इस न्यायालय के कुछ पहले के फैसलों में, बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए, यह देखा गया कि निर्दोषता की धारणा को बरी करने के आदेश से बल मिलता है और इसलिए, "निचली अदालत के निष्कर्ष जिन्हें गवाहों को देखने और उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ था, उन्हें केवल बहुत ही ठोस और सम्मोहक कारणों से ही उलट दिया जा सकता है":सूरजपाल सिंह बनाम राज्य 1952-3 एस. सी. आर. 193 पी.201 ए. आई. आर 1952 एस. सी 52।इसी तरह अजमेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1953 एस. सी. आर. 418:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 76, यह देखा गया कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और सम्मोहक कारण" हों।कुछ अन्य निर्णयों में, यह कहा गया है कि बरी करने के आदेश को केवल "अच्छे और पर्याप्त ठोस कारणों" या "मजबूत कारणों" के लिए वापस लिया जा सकता है।इन टिप्पणियों के प्रभाव की सराहना करते हुए, यह याद रखना चाहिए कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक कठोर या कठोर नियम निर्धारित करना नहीं था जो बरी होने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय को नियंत्रित करता हो।संहिता की धारा 423 (1) के खंड (ए) में एक अतिरिक्त शर्त लागू करने के लिए उनका इरादा नहीं था और न ही उनका इरादा था।उक्त टिप्पणियों का उद्देश्य केवल इस बात पर जोर देना है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए क्योंकि जैसा कि लॉर्ड रसेल ने शीओ स्वरूप के मामले में कहा था, आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा "निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं है कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है।"इसलिए, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण" अभिव्यक्ति द्वारा सुझाए गए परीक्षण को एक सूत्र के रूप में नहीं माना जाना

चाहिए जिसे हर मामले में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।यह इस न्यायालय के हाल के फैसलों का प्रभाव है, उदाहरण के लिए, संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715 और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 439 में; और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि बरी करने के फैसले को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से उसमें दर्ज निष्कर्षों को विकृत के रूप में चिह्नित करना चाहिए।इसलिए, वर्तमान अपीलों में हमें जो सवाल खुद से पूछना है, वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित हो गया था, और यह कि निचली अदालत द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण गलत था।इस प्रश्न का उत्तर देते समय, हम, निस्संदेह, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा की गई शिकायत की सराहना करने के लिए साक्ष्य की मुख्य और व्यापक विशेषताओं पर विचार करेंगे।लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत हम आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होंगे, विशेष रूप से जहां उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित हैं।

सी. एंटनी बनाम के. जी. राघवन नायर 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

“6.इस न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अपीलीय न्यायालय को उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित किया गया है, फिर भी दोषमुक्ति के मामले में ऐसी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलीय न्यायालय को न केवल तथ्य के प्रश्न और अपने दोषमुक्ति के आदेश के समर्थन में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दिए गए कारणों से संबंधित प्रत्येक मामले पर विचार करना चाहिए, बल्कि उसे निर्णय में अपने कारणों को व्यक्त करना चाहिए जिसके कारण उसे यह अभिनिर्धारित करना पड़ा कि दोषमुक्ति उचित नहीं है।उन मामलों में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि निचली अदालत को गवाहों को गवाह के कटघरा में देखने का लाभ मिला था और निर्दोष होने की धारणा बरी होने के आदेश से कमजोर नहीं होती है, और ऐसे मामलों में यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष **में बाधा नहीं डालनी चाहिए।**

देखे- भीम सिंह रूप सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (1974 (3) एस. सी. सी. 762) और धरमदेव सिंह और अन्य बनाम।बिहार राज्य (1976 (1) एस. सी. सी. 610)

[जोर दिया गया]

राजस्थान राज्य बनाम मोहन लाल 4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

“5. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को देखते हुए, हम पहले कानूनी स्थिति पर विचार करना और स्पष्ट करना उचित समझते हैं।अध्याय 21 (धारा 372 -394) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "वर्तमान संहिता" के रूप में संदर्भित) अपीलों से संबंधित है।धारा 372 स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए दंड न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होगी। धारा 373 में कुछ मामलों में अपील दायर करने का प्रावधान है।धारा 374 दोषसिद्धि से अपील की अनुमति देती है।धारा 375 उन मामलों में अपील करने पर रोक लगाती है जहां आरोपी अपना दोष स्वीकार करता है। इसी तरह, छोटे मामलों में कोई अपील विचारणीय नहीं है (धारा 376)।धारा 377 सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा अपील की अनुमति देता है।धारा 378 राज्य को बरी करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करती है।उक्त खंड सामग्री है और इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता हैः

3 2002 (4) आर. सी. आर. (सीआरएल.) 750

4 2009 (2) आर. सी. आर (सीआरएल.) 812 26

"378.दोषमुक्ति के मामले में अपील-(1) उप-धारा (2) में अन्यथा उपबंधित और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।

(2) यदि बरी करने का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा अपराध की जांच की गई है, तो केंद्र सरकार लोक अभियोजक को बरी करने के आदेश से उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का भी निर्देश दे सकती है।(3) उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, इस ओर से शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप-धारा (4) के तहत दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए किसी भी आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद विचार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता

एक लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से संगणित किया जाता है।

(6) यदि, किसी भी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उप-धारा (4) के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं होगी।

6. जबकि धारा 379-380 अपील के विशेष मामलों को शामिल करती है, अन्य धाराएं अपीलीय न्यायालयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं।

7. यह कहा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जिसे इसके बाद "पुरानी संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) में लगभग इसी तरह के प्रावधान पाए गए थे, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति और इस न्यायालय के समक्ष भी विचार के लिए आए थे।चूंकि वर्तमान अपील में, हमें बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत की शक्ति के दायरे और दायरे को तय करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने खुद को केवल एक पहलू तक सीमित कर लिया है, अर्थात बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील।

8. ऊपर उद्धृत वर्तमान संहिता की धारा 378 (बरी किए जाने के मामले में अपील) को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने में अपीलीय अदालत की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।जब ऐसी अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय को व्यापक रूप से साक्ष्य की पुनः सराहना, समीक्षा और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिस सामग्री पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है और ऐसे साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति होती है।तथ्य और कानून दोनों के सवाल उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में निर्धारण के लिए खुले हैं।

9. हालाँकि, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने की धारणा उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए।दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है और इसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाता है।

34. उपरोक्त निर्णयों से, चंद्रप्पा और ओआरएस में।कर्नाटक राज्य, 2007 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 92:2007(4) एस. सी. सी. 415), बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों को हटा दिया गया थाः

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता।दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और सुदृढ़, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

[जोर दिया गया]

लूनाराम बनाम भूपत सिंह और अन्य 5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

5 2010 (5) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 530

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

"6. अपीलीय न्यायालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उस साक्ष्य की समीक्षा करना जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश आधारित है।आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत होता है।आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, वह दृष्टिकोण जो पक्ष

में है अभियुक्त को अपनाया लिया जाना चाहिए।न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए।न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है।एक ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, अपीलीय अदालत पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह उन साक्ष्य की फिर से सराहना करे जहां आरोपी को बरी कर दिया गया है, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी आरोपी ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। (भगवान सिंह बनाम एमपी राज्य, 2003 (3) एससीसी 21 देखें।बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दखल देने की अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अदालत द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हों।यदि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और अप्रासंगिक है और इस प्रक्रिया में विश्वसनीय सामग्री को अनुचित रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण कारण है।इन पहलुओं को इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973 (2) एस. सी. सी. 793), रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996 (9) एस. सी. सी. 225), जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000 (4) एस. सी. सी. 484), राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य (2003 (11) एस. सी. सी. 519), पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह (2003 (11) एस. सी. सी. 271), पंजाब राज्य बनाम फोला सिंह (2003 (11) एस. सी. सी. 58), सुचंद पाल बनाम फनी पाल (2003 (11) एस. सी. सी. 527) और सचचे लाल तिवारी बनाम यू. पी. राज्य (2004 (11) एस. सी. सी. 410) में उजागर किया था।

[जोर दिया गया]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया है कि नागभूषण बनाम कर्नाटक राज्य 6, निम्नानुसारः

6 2021(5) एस. सी. सी 222

" 5.2 योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने से पहले बरी किए जाने के विरुद्ध अपील और धारा 378 द.प.स के दायरे और क्षेत्र और बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार किया जाना आवश्यक है।

बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189 के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 378 द.प.स 1973 में अनुछेद 12 से 19 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था।-

12. इस न्यायालय ने बार-बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार संभव हों, हालांकि अपीलीय न्यायालय का विचार अधिक संभावित हो सकता है।बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निचली अदालत के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे।अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य पर विचार करने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था।इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय हो

सकता है।(बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर बनाम बिहार राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 17, शैलेंद्र प्रताप बनाम यू. पी. राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761, नरेंद्र सिंह बनाम एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699, बुद्ध सिंह बनाम यू. पी. राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 731, यू. पी. राज्य बनाम यू. पी.राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. रामा बनाम रामी रेड्डी (2008) 5 एस. सी. सी. 535, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य (2009) 16 एस. सी. सी. 98 और राम सिंह बनाम एच. पी. राज्य (2010) 2 एससीसी 445).

13. शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 में,

प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः(आई. ए. पी. 404)

"... उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार;(2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान।

अभियुक्त, एक ऐसी धारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय न्यायालय की धीमी गति, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था।"

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

14. इस न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है।(तुलसीराम कानू बनाम राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216, एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, खेडू मोहटन बनाम बिहार राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 450, सांबशिवन बनाम केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412, भगवान सिंह बनाम एम. पी. राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 85 और गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755 देखें।

15. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415 में, इस न्यायालय ने (एस. सी. सी. P.432, पैरा 42) के तहत कानूनी स्थिति को दोहरायाः

"(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसके लिए मौलिक सिद्धांत के तहत उपलब्ध है।

आपराधिक न्यायशास्त्र कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए।दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और **सुदृढ़,**, पुनः पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।”

16. घुरेलाल बनाम यू. पी. राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450 में, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि जिन मामलों में निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया है, उनसे निपटने में अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है।अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशिष्ट लाभ था, और वह गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

17. राजस्थान राज्य बनाम नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368 में, न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की फिर से जांच की और कहा कि:(एस. सी. सी पी. 374, पैरा 20) "20. बरी किए जाने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि आरोपी की ओर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं।”

18. यू. पी. राज्य बनामबन्ने (2009) 4 एस. सी. सी. 271, इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ दीं जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायालय के लिए

उचित होगा।परिस्थितियों में शामिल हैं:(एस. सी. सी. पी. 286, पैरा 28) "(i) उच्च न्यायालय का निर्णय तय कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

(ii) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजों के विपरीत हैं।

(iii) साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर विफलता हुई।

(iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो गलत कानून और अन्य मामले के रिकॉर्ड तथ्यों पर आधारित है।

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज किया है।

" धनपाल बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 401 में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया है।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि असाधारण मामलों में जहां मजबूर करने वाली परिस्थितियां हैं, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है।अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और आगे यह कि निचली अदालत का बरी होना उसकी निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है।नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

(जो

र दिया गया)

5.2.2 जब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है, तो उपरोक्त निर्णय के अनुछेद 20 में निपटा गया है और उस पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार है:"20.न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं।निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के वजन के खिलाफ" है, या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दुष्प्रभाव से पीड़ित है।(राजिंदर कुमार किन्द्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1984) 4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम सी. सी. ई.

1994 सप्लीमेंट।(3) एस. सी. सी. 665, गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस. सी. सी. 501, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 636)"

(जोर दिया गया)

5.2.3 आगे यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद, कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1999) 2 एस. सी. सी. 10 के मामले में, यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा।लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

5.3 विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एस. सी. सी. 436 के मामले में, इस न्यायालय को धारा 378 भारतीय दंड सहिता 1973 के दायरे और बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर फिर से विचार करने का अवसर मिला।इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया।पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार माना और अभिनिर्धारित किया गया हैः

"31.उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया।इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया।उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 233) "10.एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था।आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि साक्ष्य की उचित समीक्षा के बाद उन पर निर्णय लिया जाता है। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

31.1 सम्बाशिवन बनाम कराला राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412 में, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर दोषी ठहराया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया।चाहे साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी

तरह से असमर्थनीय थे।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का आदेश विकृत था और दुर्बलता से पीड़ित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 416) "।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

8. हमने यह पता लगाने के लिए अपील के तहत निर्णय का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करता है।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबुला दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्रवाई नहीं की है, अर्थात पहले इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष उठाए गए सभी तर्कों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है।लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन स्वयं अपील के तहत फैसले को दरकिनार करने को उचित ठहराएगा?हम सोचते हैं, नहीं।हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण जो एक अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया है, खुद को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और क्या अपीलीय अदालत का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह ठहराने के लिए कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए।लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत का फैसला किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के दरकिनार फैसले को दो उचित रूप मे अलग करना होगा। विचार, जो बरी होने के समर्थन में है, उसे कायम रखना होगा।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

31.2.के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम कराला राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 309 वाले मामले में, यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद खारिज

करने से इनकार कर दिया कि बरी करने के आदेश को दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और कई पहलुओं पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया निष्कर्ष अस्थिर था।इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करने में उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से अधिकार था।इस अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पेश किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3.एटली बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807 में, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः (ए.आई.आर पीपी. 809-10)।

"5.अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की केवल सराहना पर इसे तब तक दरकिनार नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि निचली अदालत के न्यायाधीश का फैसला विकृत था।हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत धारा 417 भारतीय दंड सहिता के तहत एक अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी होने का निर्णय विकृत था, वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर उच्च न्यायालय के लिए खुला है। सम्पूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आना, निश्चित रूप से, इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय से मजबूत होती है, जिसे उन गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था जिनके साक्ष्य उनकी उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील न्यायालय को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में साक्ष्य की सराहना करने की उतनी ही व्यापक शक्तियां हैं जितनी कि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, बशर्ते कि निर्दोष होने का अनुमान जिसके साथ अभियुक्त व्यक्ति निचली अदालत में शुरू होता है, अपीलीय चरण तक जारी रहता है और यह कि अपीलीय अदालत को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने बरी करने का आदेश दर्ज किया था।

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है।(इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 52; विलायत खान बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई

सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं था।

के. गोपाल रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355 में, इस न्यायालय ने कहा है कि जहां निचली अदालत खुद को काल्पनिक संदेहों से घेरने की अनुमति देती है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज कर देती है और साक्ष्य को ध्यान में रखती है जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन का उपहास किया जाए।

[जोर दिया गया]

करण आनंद बनाम कमल बख्शी 7 के मामले में इस अदालत ने कहा कि

इसके अंतर्गतः-

“5. इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को विकृत या इसके विपरीत अभिलेख सामग्री नहीं कहा जा सकता है।वास्तव में अभियुक्त/प्रत्यर्थी को बरी करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क में कोई दुर्बलता नहीं है।यह एक स्थापित कानून है जैसा कि सी. एंटनी बनाम में माना गया है। के. जी. राघवन नायर, 2002 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 750 ने कहा कि भले ही साक्ष्य के मूल्यांकन पर दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, अदालत अभियुक्त को बरी करने में हस्तक्षेप नहीं करेगी।बरी किए जाने के मामलों में, उसके पक्ष में दोहरी धारणा है; पहला निर्दोष होने का अनुमान, और दूसरा अभियुक्त के बरी होने के बाद, न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह निर्णायक रूप से नहीं दिखाया जाता है कि अपराध का निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है।

[जोर दिया गया]

7 2015 (4) आर. सी. आर. (सीआरएल.) 595

रेखा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 8, निम्नानुसार आयोजितः- “13.आवेदन की गई अनुमति देते समय, इस न्यायालय को यह ध्यान रखना है कि बरी होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता है।दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती है, लेकिन निचली अदालत द्वारा फिर से लागू, पुष्टि और मजबूत की जाती है।जब अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव होते हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।”

[(16) माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णय इस आशय के हैं कि जहां एक अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा करने, पुनः मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिसके आधार पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है, यह भी उतना ही सत्य है कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दोहरी धारणा है, पहला अभियुक्त के लिए उपलब्ध निर्दोषता के अनुमान के कारण और दूसरा इस तथ्य के कारण कि सक्षम न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया है और इसलिए, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव थे, तो अपीलीय न्यायालय को नहीं करना चाहिए।विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को केवल इसलिए बाधित करता है, क्योंकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की तुलना में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था।हालांकि, जहां इसके खिलाफ अपील किया गया निर्णय पूरी तरह से विकृत है और प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक या अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा गया है, तो अपीलीय न्यायालय उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें दरकिनार करने की अपनी शक्तियों के भीतर होगा।

8 2019 (4) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 294

विरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 39

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

(17) ऊपर की विस्तृत चर्चा के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को बरी करते समय विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर एक उचित दृष्टिकोण है, जिसे विकृत नहीं कहा जा सकता है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(18) इसलिए, यह न्यायालय विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखता है और इसलिए अपील करने की अनुमति देने का आवेदन एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

दिव्या गुर्ने

रीतू सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।